

## कृषि नीति निगिरानी और मूल्यांकन 2024

### प्रलिस के लयः

[आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, बाज़ार मूल्य समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य](#)

### मेन्स के लयः

सरकारी खरीद और वतऱरण का प्रभाव, सरकारी नीतयऱँ और पहल, कृषि नीतऱँ और भारतीय कसऱनों पर इसका प्रभाव

[स्रोतः डाउन टू अर्थ](#)

### चर्चा में क्यऱँ?

हाल ही में, [आर्थिक सहयोग और विकास संगठन \(OECD\)](#) द्वारा अपनी [2024](#) में बताया गया है कऱँ भारत वर्ष 2023 में अपने कसऱनों पर 120 बलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर का कर लगाएगा, जो 54 देशऱँ में सबसे अधकऱ है ।

- यह नरऱयात प्रतऱबऱध और शुल्क जैसी सरकारी नीतयऱँ का उद्देश्य उद्देश्यउपभोक्ताऱँ के लयऱ खऱद्य कऱमतऱँ को कम रखना है, लेकनऱ इससे कृषऱ क्षेत्र पर भारऱ वतऱतऱयऱँ बऱझ बढ़ता है ।

### OECD की रऱऱरऱ की मुखय बऱतें क्यऱ हैं?

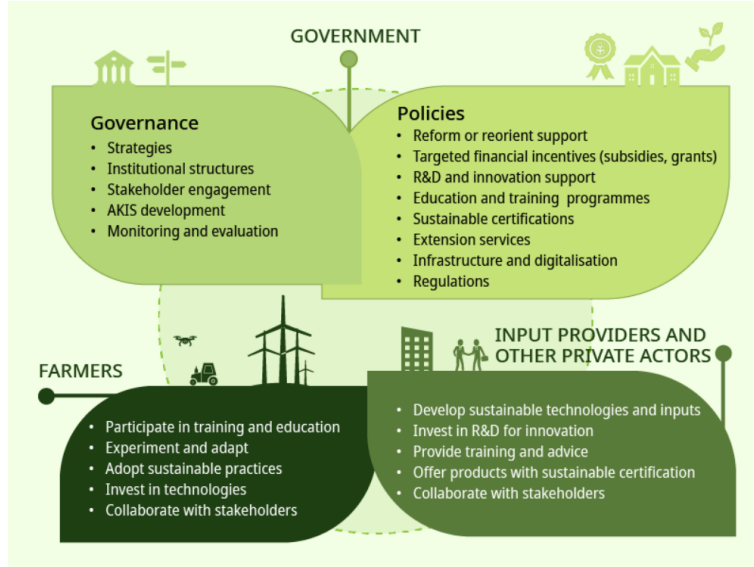
- कृषऱ में वतऱतऱयऱ सहायताः वर्ष 2021 से 2023 तक 54 देशऱँ में कृषऱ क्षेत्र के लयऱ कुल सहायता औसतन 842 बलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर प्रतऱ वर्ष रही है । यद्दयऱपर वर्ष 2021 के शखऱर की तुलना में वर्ष 2022 और 2023 में इसमें गरऱवट आई, फरऱ भी यह [कोवडऱ-19 महऱमऱरी](#) से पहले के स्तर से काफऱी अधकऱ है ।
- वर्ष 2021-23 के बीच बाज़ार मूल्य समर्थन (MPS) में 28 बलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर की गरऱवट आई, लेकनऱ फरऱ भी यह कुल समर्थन का एक बड़ा हसऱसा बना रहा ।
  - MPS एक नीतऱगऱत उपाय है जसऱका उद्देश्य घरेलू बाज़ार में कसऱी वशऱषऱट कृषऱ उत्पाद की कऱमत को एक नशऱऱतऱ न्यूनतम (सरकार द्वारा नरऱधऱरतऱ) स्तर पर बनाए रखना है, जसऱसे घरेलू कऱमतऱँ को वशऱव कऱमतऱँ से ऊपर उठने में मदद मलऱेगी ।
- भारत में कृषऱ सहायताः वर्ष 2023 में चावल, चीनी, प्याज और तेल रहतऱ चावल की भूसऱ पर भारत के नरऱयात प्रतऱबऱधऱँ के कारण MPS नकारऱतऱमक हो गया, जसऱसे 110 बलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर का नुकसान हुआ ।
- परगऱमसवरूप, कसऱनों को उनकी उपज के लयऱ उतना मूल्य नहीं मलऱा जतऱना इन नीतयऱँ के बनऱा मलऱता, जसऱसे उनकी आय में उल्लेखनीय कमी आई ।
- वर्ष 2023 में भारत का समग्र बाज़ार मूल्य समर्थन नकारऱतऱमक था, जसऱसे 110 बलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर का नुकसान हुआ, जसऱका अर्थ है कऱ कसऱनों को उनकी उपज के लयऱ मूल्य उतना नहीं मलऱा जतऱना उनहें इन नीतयऱँ के बनऱा मलऱता था ।
  - भारत में सबसे ज़्यादा नकारऱतऱमक मूल्य समर्थन था, उसके बाद वयऱतनाम और अर्जेंटीना का स्थऱन था । वर्ष 2023 में वैश्वकऱ नकारऱतऱमक मूल्य समर्थन में भारत का हसऱसा 62.5% था । यह हसऱसा 2000-02 में 61% से बढ़कर 2021-23 में 75% हो गया है, जो भारतीय कसऱनों पर बढ़ते बऱझ को दर्शाता है ।
  - सबसऱडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माधयम से कुल 10 बलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर के सकारऱतऱमक समर्थन के बावजूद, मूल्य-नरऱशाजनक नीतयऱँ ने इन उपायऱँ को के प्रभाव को कम कर दऱया ।
- वैश्वकऱ कृषऱ चुनऱतयऱँः चल रहे संघर्षऱँ (जैसे कऱ [युक्रेन के खलऱफ रूस का युद्ध](#) और [मध्य पूरव में अशांतऱ](#)) ने कृषऱ बाज़ारऱँ को बाधतऱ कऱया है, जसऱने वशऱषऱ रूप से वऱयापऱर और वैश्वकऱ आपूर्तऱ शृंखलाऱँ को प्रभावतऱ कऱया है ।
- चरम मौसमी घटनाऱँ की बढ़ती आवृत्तऱ और गंभीरता, कृषऱ उत्पादन एवं उत्पादकता के लयऱ चुनऱतऱ बनी हुई है ।
- कुछ देशऱँ के नरऱयात प्रतऱबऱध से कृषऱ वस्तुऱँ का अंतरऱराषटऱरीय वऱयापऱर और अधकऱ वकऱत हो गया है ।
- वऱभिन्न देशऱँ में कसऱनों के बढ़ते वरऱोध प्रदर्शन से कसऱनों के आर्थकऱ एवं सामऱजकऱ संघर्ष पर प्रकाश पड़ता है ।
- वैश्वकऱ कृषऱ उत्पादकता की वृद्धऱ धऱमी होने से स्थऱरऱता बनाए रखते हुए बढ़ती वैश्वकऱ खऱद्य मांगऱँ को पूरा करना जटलऱ हो गया है ।
- सरकारें भुगतऱन को कृषऱ पद्धतयऱँ से जोड़ रही हैं जसऱसे भूमऱ स्वास्थयऱ, [जैववऱधऱता](#) और स्थऱरऱता को समर्थन मलऱता है, लेकनऱ परऱयावरणीय

सार्वजनिक वस्तु भुगतान (EPGP) कुल उत्पादक समर्थन का केवल 0.3% है।

◦ EPGP पर्यावरण को लाभ पहुँचाने वाले सार्वजनिक कर्षत्रों (जैसे **जलवायु संरक्षण**) को वित्तपोषित करने का एक तरीका है।

- **दशा-नरिदेश:** सरकारों को धारणीय उत्पादकता हेतु मापनीय लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है तथा **कुल कारक उत्पादकता (TFP)** एवं **कृषि-पर्यावरण संकेतक (AEIs)** जैसी नगिरानी प्रणालियों में नविश करना चाहिये।
- TFP द्वारा कृषि इनपुट की दक्षता को मापा जाता है। TFP वृद्धि दर्शाती है कि किसान समान या कम संसाधनों से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जो इसे धारणीय कृषि हेतु एक महत्वपूर्ण उपागम बनाता है।
- **AEIs** से कृषि से होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय प्रभावों और जोखिमों को मापने के साथ उत्पादकों के प्रबंधन के तरीकों का आकलन किया जाता है। ये कृषि के प्रदर्शन एवं इसके अंतरनिहित कारणों को समझाने में भी सहायक हैं।
- **इस रिपोर्ट में उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में नवाचार** की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के साथ उत्पादन का प्रमुख भाग **धारणीय कृषि पद्धतियों** से जोड़ने का आह्वान किया गया है।

// What governments, farmers and others are doing for sustainable productivity growth



Source: OECD (2024), OECD Agricultural Policy Monitoring and Evaluation: Innovation for Sustainable Productivity Growth (Figure 1.13)

## आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) क्या है?

- **परिचय:**
  - OECD एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति व विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है।
  - अधिकांश OECD सदस्य राष्ट्र उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनका **मानव विकास सूचकांक (HDI)** बहुत उच्च है एवं उन्हें विकसित देश माना जाता है।
- **स्थापना:**
  - इसके मुख्यालय की स्थापना वर्ष 1961 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी तथा इसमें कुल 38 सदस्य देश हैं।
  - OECD में शामिल होने वाले सबसे हालिया देश थे- अप्रैल 2020 में कोलंबिया तथा मई 2021 में कोस्टा रिका।
  - भारत इसका सदस्य नहीं है अपितु एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है।
- **OECD द्वारा जारी रिपोर्ट और सूचकांक:**
  - गवर्नमेंट एट अ ग्लॉस
  - OECD बेटर लाइफ इंडेक्स

## भारतीय कृषि नीतियाँ किसानों पर नकारात्मक प्रभाव कैसे डालती हैं?

- **नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन:** भारत की नीतियों के परिणामस्वरूप किसानों के लिये नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन हुआ है। वर्ष 2014 से 2016 तक, उत्पादक समर्थन अनुमान (PSE) लगभग -6.2% था, जो नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन (-13.1%) से प्रेरित था।
  - PSE एक मीटरिक है जो उपभोक्ताओं और सरकार से कृषि उत्पादकों को होने वाले हस्तांतरण के वार्षिक मूल्य को मापता है।
- **नरियात प्रतिबंध और रोक:** चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर नरियात प्रतिबंध और कोटा लगाने से बाजार तक पहुँच सीमित हो जाती है, जिससे घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं।

- नयामक बाधाएँ: **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** और **कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (APMC) अधिनियम 2003** कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, भंडारण और व्यापार पर कठोर नियम लागू करते हैं।
  - यद्यपि इन अधिनियमों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नियंत्रण और कम खरीद मूल्यों के कारण अक्सर कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो जाती हैं, जो कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मूल्यों से भी कम होती हैं, जिससे उत्पादकों पर मूल्य-नरिशाजनक प्रभाव पड़ता है।
- कम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): MSP का उद्देश्य किसानों की रक्षा करना है, लेकिन कुछ अवधियों के दौरान इसे अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से भी कम निर्धारित किया गया है, जिसके कारण किसानों को खुले बाज़ार की तुलना में कम मूल्य प्राप्त हो रहा है।
- वणिगण में अकुशलताएँ: आधुनिक बुनियादी ढाँचे की कमी और उच्च लेन-देन लागत के कारण किसानों को उनकी उपज के लिये मलिन वाली कीमतें कम हो जाती हैं, जिससे मूल्य दमन को बढ़ावा मिलता है।
- अकुशल संसाधन आवंटन: उर्वरक, संचाई और बजिली के लिये सब्सिडी अल्पकालिक राहत प्रदान करती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, बाज़ार पहुँच और कृषि अनुसंधान में गिरावट जैसे दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने में वफ़िल रहती है, जो अंततः किसानों के लिये सतत विकास और लाभप्रदता में बाधा उत्पन्न करती है।

## कृषि से संबंधित भारत की पहल

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- कृषि विानकी पर उप-मिशन (SMAF)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- एग्रीसटैक
- डिजिटल कृषि मिशन
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)
- प्रवोत्तर कषेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

## आगे की राह

- नरियात नीतियों में सुधार: नरियात प्रतबंधों और कोटा को धीरे-धीरे कम करना, बुनियादी ढाँचे शीत भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण) में निवेश करना तथा प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देने और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिये MSP को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मूल्यों के अनुरूप बनाना।
- बजटीय प्राथमिकताओं में बदलाव: लचीलेपन, स्थिरता, बुनियादी ढाँचे में सुधार और आपूर्ति शृंखला की अकुशलताओं को कम करने की दशा में संसाधनों को पुनर्निदेशित करना।
- बेहतर बाज़ार कार्यप्रणाली: समन्वय में सुधार, वखिंडन को कम करने और कषेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिये राज्य और केंद्रीय नीतियों के बीच अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना: किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिये **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम)** जैसे प्रत्यक्ष वणिगण और ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित करना, जिससे पारंपरिक बाज़ारों पर निर्भरता कम हो।

???????? ???? ???? ????:

**प्रश्न:** भारत की कृषि नीतियों का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा कीजिये। नरियात प्रतबंध और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी नीतियाँ कृषि कषेत्र को कैसे प्रभावित करती हैं?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????????:

**प्रश्न:** भारत में, नमिनलखिति में से कनिहें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? (2020)

1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण
3. सामाजिक पूंजी विकास
4. कृषकों को निःशुल्क बजिली की आपूर्ति
5. बैंकगि प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी
6. सरकारों द्वारा शीतागार सुवधियों को स्थापित करना

निचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
- (b) केवल 1, 3, 4 और 5
- (c) केवल 2, 3 और 6

(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न: भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर, फसल बीमा की आवश्यकता की विचारना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी० एम० एफ० बी० वाइ०) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। (2016)

प्रश्न: भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिये। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है? (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2024>

